SAFALTA CLASS™

An Initiative by अमर उजाला

INDIAN

POLITY

BY – SUJEET BAJPAI SIR

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

Appointment of Judges

कोलेजियम सिस्टम
(CJI + 2 Sen. Judge)

The judges of the Supreme Court are appointed by the president.

The chief justice is appointed by the president after consultation with such judges of the Supreme Court and high courts as he deems necessary.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

न्यायाधीशों की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है जैसा कि वह आवश्यक समझे ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Qualifications of Judges

A person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications:

1. He should be a citizen of India.

2. (a) He should have been a judge of a High Court (or high courts in succession) for five years; or

(b) He should have been an advocate of a High Court (or High Courts in succession) for ten years;

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

न्यायाधीशों की योग्यता

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

2. (क) उन्हें पांच वर्षों तक उच्च न्यायालय (या उत्तराधिकार में उच्च न्यायालयों) का न्यायाधीश होना चाहिए था; या

(ख) उन्हें दस वर्षों तक उच्च न्यायालय (या उत्तराधिकार में उच्च न्यायालयों) का अधिवक्ता होना चाहिए था;

or (c) He should be a distinguished jurist in the opinion of the president.

From the above, it is clear that the Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as a judge of the Supreme Court.

या (ग) राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए ।

ऊपर से यह स्पष्ट है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।

Tenure of Judges

The Constitution has not fixed the tenure of a judge of the Supreme Court.

However, it makes the following three provisions in this regard:

1. He holds office until he attains the age of 65 years. Any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manner as provided by Parliament.

Max Age

न्यायाधीशों का कार्यकाल

संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का कार्यकाल तय नहीं किया है। हालांकि, यह इस संबंध में निम्नलिखित तीन प्रावधान करता है:

1. वह तब तक पद धारण करता है जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ले। उनकी आयु के संबंध में कोई भी प्रश्न ऐसे प्राधिकारी द्वारा और संसद द्वारा प्रदान किए गए इस प्रकार से निर्धारित किया जाना है ।

2. He can resign his office by writing to the president.

3. He can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament.

2. वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

3. संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है।

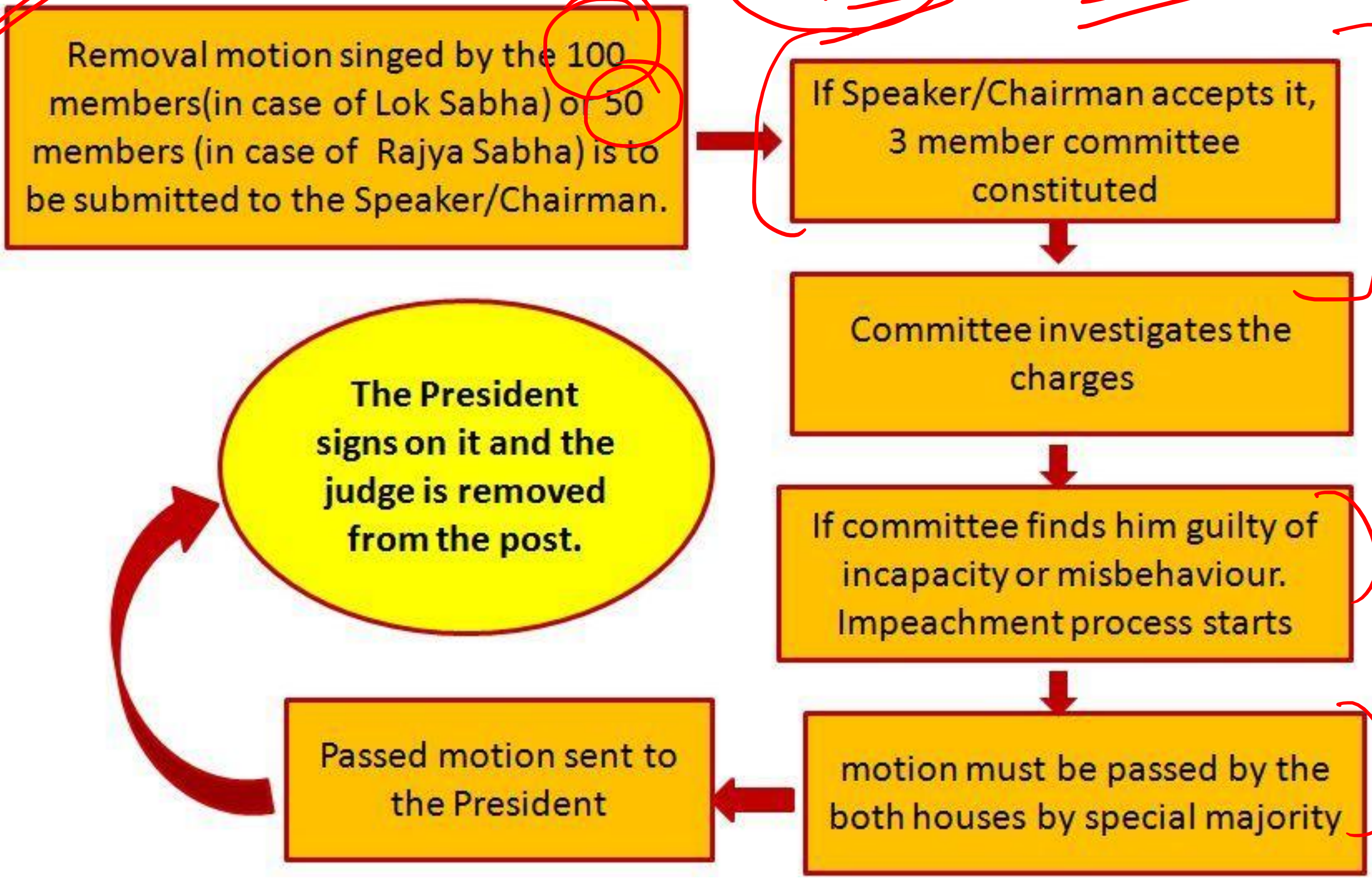
Removal motion singed by the 100 members(in case of Lok Sabha) or 50 members (in case of Rajya Sabha) is to be submitted to the Speaker/Chairman.
If Speaker/Chairman accepts it, 3 member committee constituted
Committee investigates the charges
If committee finds him guilty of incapacity or misbehaviour. Impeachment process starts
motion must be passed by the both houses by special majority
Passed motion sent to the President
The President signs on it and the judge is removed from the post.

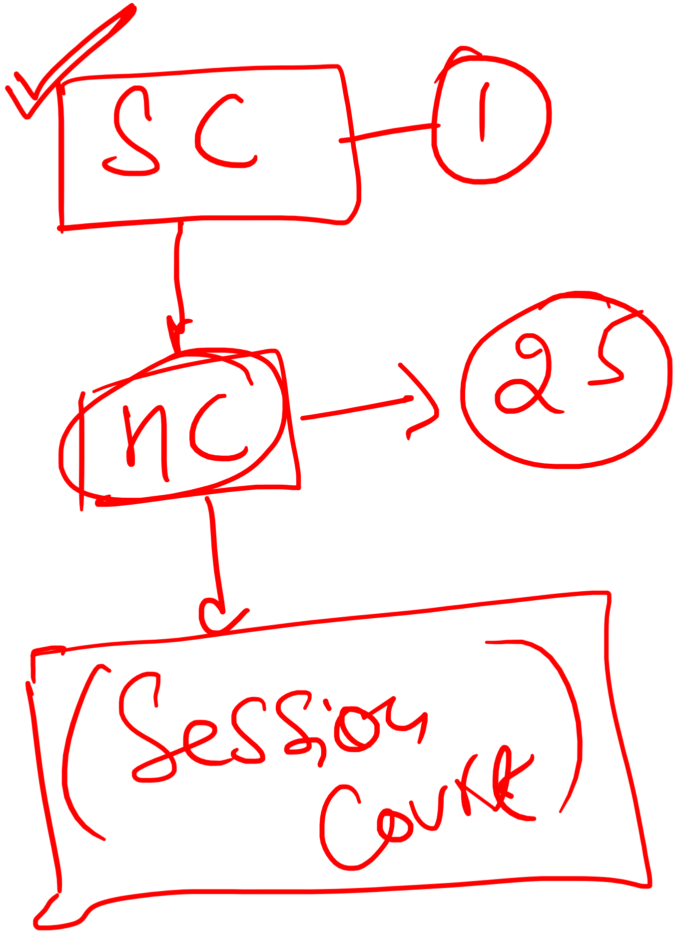
SC
1
NC
25
Session Court

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Jurisdiction and Powers of Supreme Court

1. Original Jurisdiction.
2. Writ Jurisdiction.
3. Appellate Jurisdiction.
4. Advisory Jurisdiction.
5. A Court of Record.
6. Power of Judicial Review.
7. Other Powers.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार और शक्तियां

1. मूल क्षेत्राधिकार।
2. रिट क्षेत्राधिकार।
3. अपीलीय क्षेत्राधिकार।
4. सलाहकार क्षेत्राधिकार।
5. रिकॉर्ड की एक अदालत ।
6. न्यायिक समीक्षा की शक्ति।
7. अन्य शक्तियां।

1. Original Jurisdiction

As a federal court, the Supreme Court decides the disputes between different units of the Indian Federation. More elaborately, any dispute between:

(a) the Centre and one or more states; or

1. मूल क्षेत्राधिकार

संघीय अदालत के रूप में सुप्रीम कोर्ट भारतीय महासंघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृत रूप से, के बीच किसी भी विवाद:

(क) केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य; या

AG

Approve

[Contempt of Court]

Art - 129

IRs

(b) the Centre and any state or states on one side and one or more states on the other; or

(c) between two or more states.

(ख) केंद्र और एक तरफ कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य; या

(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ।

2. Writ Jurisdiction

The Constitution has constituted the Supreme Court as the guarantor and defender of the fundamental rights of the citizens.

2. रिट क्षेत्राधिकार

संविधान ने सुप्रीम कोर्ट का गठन नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गारंटर और रक्षक के रूप में किया है।

3. Appellate Jurisdiction

As mentioned earlier, the Supreme Court has not only succeeded the Federal Court of India but also replaced the British Privy Council as the highest court of appeal.

The Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeals against the judgements of the lower courts.

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्चतम न्यायालय ने न केवल भारत के संघीय न्यायालय को सफलता दी है बल्कि ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को सर्वोच्च अपील अदालत के रूप में भी प्रतिस्थापित किया है ।

सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से अपील की अदालत है और निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under four heads:

(a) Appeals in constitutional matters.

(b) Appeals in civil matters.

(c) Appeals in criminal matters.

(d) Appeals by special leave.

यह एक व्यापक अपीलीय क्षेत्राधिकार है जो चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है प्राप्त है:

(क) संवैधानिक मामलों में अपील।

(ख) सिविल मामलों में अपील ।

(ग) आपराधिक मामलों में अपील।

(घ) विशेष अवकाश द्वारा अपील ।

Appeal by Special Leave (Article 136)

The Supreme Court is authorised to grant in its discretion special leave to appeal from any judgement in any matter passed by any court or tribunal in the country (except military tribunal and court martial).

विशेष अवकाश द्वारा अपील (अनुच्छेद 136)

सुप्रीम कोर्ट देश में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी मामले (सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर) द्वारा पारित किसी भी फैसले से अपील करने के लिए अपने विवेक विशेष अवकाश में अनुदान देने के लिए अधिकृत है।

4. Advisory Jurisdiction

The Constitution (Article 143) authorises the president to seek the opinion of the Supreme Court in the two categories of matters:

(a) On any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise.

(b) On any dispute arising out of any pre-constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanador other similar instruments

4. सलाहकार क्षेत्राधिकार संविधान (अनुच्छेद १४३)

राष्ट्रपति को मामलों की दो श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए अधिकृत करता है:

(क) कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ है या जो उत्पन्न होने की संभावना है ।

(ख) किसी भी पूर्व संविधान संधि, समझौते, वाचा, सगाई, संयोजिका अन्य समान साधनों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर

In the first case, the Supreme Court may tender or may refuse to tender its opinion to the president. But, in the second case, the Supreme Court 'must' tender its opinion to the president.

In both the cases, the opinion expressed by the Supreme Court is only advisory and not a judicial pronouncement.

Hence, it is not binding on the president; he may follow or may not follow the opinion.

पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट टेंडर कर सकता है या राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकता है ।

लेकिन, दूसरे मामले में, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी राय का टेंडर देना चाहिए ।

दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकारी है न कि न्यायिक घोषणा। इसलिए, यह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है; वह का पालन करें या राय का पालन नहीं कर सकते हैं ।

Source → USA

Judicial Activism

father → P. N. Bhagwati (P)

K. Iyer

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

In India, the PIL is a product of the judicial activism role of the Supreme Court.

It was introduced in the early 1980s by Justice V.R. Krishna Iyer and Justice P.N. Bhagwati.

भारत में यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता की भूमिका की उपज है।

इसे 1980 के दशक की शुरुआत में जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर और जस्टिस पीएन भगवती ने पेश किया था ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Justice Fathima Beevi became the first female judge who was appointed to the Supreme Court of India in 1989.

High Courts in India

Articles 214 to 231 in Part VI of the Constitution deal with the organisation, independence, jurisdiction, powers, procedures and so on of the high courts.

संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 214 से 231 संगठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार, शक्तियां, प्रक्रियाएं आदि उच्च न्यायालयों के साथ संबंधित हैं।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

The institution of high court originated in India in 1862 when the high courts were set up at Calcutta, Bombay and Madras.

In 1866, a fourth high court was established at Allahabad.

There are 25 High Courts in India.

उच्च न्यायालय की संस्था का उदभव 1862 में भारत में हुआ था जब कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी।

1866 में इलाहाबाद में एक चौथा हाईकोर्ट की स्थापना हुई।

भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।

List of High Courts in India

Year	Name	Territorial Jurisdiction	Seat & Bench
1862	Bombay	Maharashtra Dadra & Nagar Haveli Goa Daman Diu	Seat: Mumbai Bench: Panaji, Aurangabad, and Nagpur
1862	Kolkata	West Bengal Andaman & Nicobar islands	Seat: Kolkata Bench: Port Blair
1862	Madras	Tamil Nadu Pondicherry	Seat: Chennai Bench: Madurai

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

1866	Allahabad	Uttar Pradesh	Seat: Allahabad Bench: Lucknow
1884	Karnataka	Karnataka	Seat: Bengaluru Bench: Dharwad and Gulbarga
1916	Patna	Bihar	Patna
1928	Jammu & Kashmir	Jammu & Kashmir	Srinagar and Jammu

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

1948	Guwahati	Assam Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh	Seat: Guwahati Bench: Kohima, Aizawl, and Itanagar
1949	Odisha	Odisha	Cuttack
1949	Rajasthan	Rajasthan	Seat: Jodhpur Bench: Jaipur
1956	Madhya Pradesh	Madhya Pradesh	Seat: Jabalpur Bench: Gwalior and Indore
1958	Kerala	Kerala & Lakshadweep	Ernakulam
1960	Gujarat	Gujarat	Ahmedabad
1966	Delhi	Delhi	Delhi

1971	Himachal Pradesh	Himachal Pradesh	Shimla
1975	Punjab & Haryana	Punjab, Haryana & Chandigarh	Chandigarh
1975	Sikkim	Sikkim	Gangtok
2000	Chattisgarh	Chattisgarh	Bilaspur
2000	Uttarakhand	Uttarakhand	Nainital
2000	Jharkhand	Jharkhand	Ranchi

2013	Tripura	Tripura	Agartala
2013	Manipur	Manipur	Imphal
2013	Meghalaya	Meghalaya	Shillong
2019	Telangana	Telangana	Hyderabad
2019	Andhra Pradesh	Andhra Pradesh	Amravati

The Constitution of India provides for a high court for each state, but the Seventh Amendment Act of 1956 authorised the Parliament to establish a common high court for two or more states or for two or more states and a union territory.

भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, लेकिन 1956 के सातवें संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Article No.	Subject Matter
214.	High Courts for states
215.	High Courts to be courts of record
216.	Constitution of High Courts

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

223.	Appointment of acting Chief Justice
224.	Appointment of additional and acting judges
224A.	Appointment of retired judges at sittings of High Courts
225.	Jurisdiction of existing High Courts
226.	Power of High Courts to issue certain writs
226A.	Constitutional validity of Central laws not to be considered in proceedings under Article 226 (Repealed)

Jurisdiction and Powers of High Court

At present, a high court enjoys the following jurisdiction and powers:

1. Original jurisdiction.
2. Writ jurisdiction. — Art- 226

3. Appellate jurisdiction.
4. Supervisory jurisdiction.
5. Control over subordinate courts.
6. A court of record.
7. Power of judicial review.

1. Original Jurisdiction

It means the power of a high court to hear disputes in the first instance, not by way of appeal. It extends to the following:

(a) Matters of admirality, will, marriage, divorce, company laws and contempt of court

1. मूल क्षेत्राधिकार इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय की पहली बार में विवादों की सुनवाई करने की शक्ति, अपील के माध्यम से नहीं ।

यह निम्नलिखित तक फैली हुई है:

(क) एडमिरलिटी, इच्छा, विवाह, तलाक, कंपनी कानून और न्यायालय की अवमानना के मामले

(b) Disputes relating to the election of members of Parliament and state legislatures.

(c) Regarding revenue matter or an act ordered or done in revenue collection.

(d) Enforcement of fundamental rights of citizens.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

(ख) संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित विवाद।

(ग) राजस्व मामले या राजस्व वसूली में आदेशित या किए गए अधिनियम के संबंध में।

(घ) नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करना।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

Appointment of Judges The judges of a high court are appointed by the President.

The chief justice is appointed by the President after consultation with the chief justice of India and the governor of the state concerned.

न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है।

For appointment of other judges, the chief justice of the concerned high court is also consulted.

In case of a common high court for two or more states, the governors of all the states concerned are consulted by the president.

अन्य जजों की नियुक्ति के लिए संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है।

दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक आम उच्च न्यायालय के मामले में, संबंधित सभी राज्यों के राज्यपालों से राष्ट्रपति द्वारा परामर्श किया जाता है ।

Qualifications of Judges

A person to be appointed as a judge of a high court, should have the following qualifications:

1. He should be a citizen of India.

2. (a) He should have held a judicial office in the territory of India for ten years; or

(b) He should have been an advocate of a high court (or high courts in succession) for ten years.

न्यायाधीशों की योग्यता एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

2.

(क) उन्हें दस वर्षों तक भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करना चाहिए था; या

(ख) उन्हें दस वर्षों तक उच्च न्यायालय (या उत्तराधिकार में उच्च न्यायालयों) का अधिवक्ता होना चाहिए था ।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला